(c) Industrial licence applications have been rejected on any one or more of the following grounds:—

(i) No scope for creation of additional capacity in the proposed item of manufacture.

(ii) Proposal is not economically viable|technically sound| not well formulated.

(iii) Proposed item of manufacture is reserved for public sector/ small scale sector|de-licensed.

(iv) Proposal is not covered under the current policy guidelines.

(v) Based on imported raw material.

(vi) Highly polluted industry and its item of manufacture is hazardous.

(vii) Proposal does not conform to the locational policy of the Government, etc.

Foreign collaboration and their investments

2827. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the country-wise break-up of the foreign collaborations approved during 1986 and 1987; and

(b) the country-wise break-up of foreign investments approved during 1986 and 1987?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Statement showing country-wise break-up of foreign collaborations and investment approved during and 1987 are enclosed as anntxure [*See* Appendix CXLIX, Annexure No. 156]

लघु उद्योगों को दी गयी वित्तीय सहायता का वापस किया जाना

2828. **श्री अशोक नाथ वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने मूल उद्देश्य से पीछे हटने पर पुनः विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को आवंटित किए गए धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्र सरकार अनुपत्र में दर्शायी गयी तथा उसमें दी गई टिप्पणियों के अधीन लघु एककों को दी जा रही विद्यमान वित्तीय सहायता को वापस लेने पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्यों को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार योजना (एस०ई०ई०यू०वाई०) रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु सीमान्त धनराशि योजना तथा इंजीनियर उद्यमियों को ब्याज राजसहायता (31-3-1985 से बंद कर दी गई है किन्तु राज्यों को शेष दावों की प्रतिपूर्ति की जा रही है) जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है। एस०ई०ई०यू०वाई योजना के अधीन केन्द्र सरकार प्रत्येक ऋण पर 25 प्रतिशत पूंजीगत राजसहायता दे रही है। उक्त राजसहायता भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दी जाती है। 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान इन योजनाओं के अधीन लघु एककों को दी गई वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं। [**देखिये** परिशिष्ट 149, अनुपत्र सं० 157]

घरेलू गैस वितरकों के साथ भेदभाव पूर्ण बर्ताव

2829. **श्री सुनील कुमार पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी दिल्ली में घरेलू गैस वितरकों द्वारा उनक

एल०पी०जी० सिलिंडर के स्टाक समाप्त होने पर समय पर बैंक-ड्राफ्ट जमा करवाये जाने के बावजूद भी उन्हें समय पर सिलिंडर सप्लाई नहीं किए जाते जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को शहर के अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के मुकाबले एल०पी०जी० सिलिंडर समय पर प्राप्त नहीं होते; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, नहीं। सामान्यतया वितरकों के इंडेंटों पर तेल कम्पनियों द्वारा देय तारीख को ही कार्य किया जाता है सिवाय प्रचालन संबंधी रुकावट के ऐसे समय में जब कुछ देरी होने की संभावना होती है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Kelkar Committee Report

2830. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Supplementary Report of the Kelkar Committee has been submitted to Government; if so, when it is proposed to be laid before Parliament;

(b) what are the recommendations made by the said Committee and whether Government have examined these recommendations; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (c) the required details to the extent available have been given in reply to Starred Question 77 answered on on 27-2-1989.

Estimated requirement of crude and petroleum products

2831. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the estimated requirement of crude and petroleum products during 1989-90;

(b) what is the estimated oil output in the country during 1989-90;

(c) what is the net out go on account of oil imports during 1988-89; and

(d) what steps are proposed to intensify exploration of oil and to create the facilities for the use of nautral gas?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) The estimated crude processing requirement of crude oil and demand of petroleum products are estimated to be 50.959 million tonnes and 54.161 million tonnes respectively during the year 1989-90.

(b) The availability of indigenous crude for processing is estimated to be about 33.1 million tonnes during 1989-90.

(c) The net value of the import of crude oil and petroleum products is estimated to be Rs. 3672 crores during 1988-89.

(d) The following steps have been taken to increase the production of crude oil:

— Intensification of erploration, which may eventually lead to enhanced production.

— Use of enhanced oil recovery techniques.

— Induction of advanced technology.

As far as natural gas is concerned, schemes for exploiting natural gas potential are drawn up from time to time depending upon the availability of gas and techno-economic viability of its exploitation.

Growth of paint industry

2832. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what has been the growth of the paint industry during the last three years, year-wise;